(b) whether any difficulties have been encountered in implementing the policy; and

(c) whether Government propose to sponsor a series of colloquia to discuss the modalities for improving language teaching at the primary level?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Dr. Radhakrishan Commission was concerned with University education and made no recommendation regarding the teaching of languages at the primary stage.

The Kothari Commission (1964—66) had recommended the introduction of one language i.e. the mother tongue or the regional language at the stage of primary education (Class I to IV). This recommendation was accepted in the statement on National Policy on Education issued by the Government of India in 1968.

Generally speaking, this recommendation has been implemented throughout the country.

While mother tongue is used as medium of instruction, regional language has also been introduced at upper primary stage in many of the States/Union Territories. In some parts of the country, like Sikkim, Nagaland and Mizoram, English is taught as the first language and as a medium of instruction.

(b) There have been no difficulties encountered in implementing the policy regarding the introduction of mother tongue/regional language at the primary stage.

(c) The Government and the educational agencies at national and state levels have been making efforts to improve language education at the primary level as a part of the nation-wide efforts to improve the quality of primary education.

Bill to make Primary Education Compulsory

1155. SHRI JANESHWAR MISRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government intend to bring forward a Bill to make primary education compulsory;

(b) if so, by when and whether the Bill will be binding on both Government and Non-Government institutes;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) The Constitution (Eighty-Third Amendment) Bill, 1997 to make right to free and compulsory education for children in the age-group of 6 to 14 years a Fundamental Right was introduced in the Rajya Sabha on July 28, 1997.

The Bill, inter-alia, provides that the State shall not make any law for free and compulsory education in relation to educational institutions not maintained by the State or not receiving aid out of State funds.

The report of the Parliamentary Standing Committee on the Constitution (Eighty Third Amendment) Bill, 1997 is under examination. It is felt that a wider debate on the implications of the proposed legislation should be initiated.

विश्वविद्यालय-निधियों के दुरुपयोग की सी० बी० आई० द्वारा जांच किया जाना

1156. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय निधि तथा गैर-योजना शीर्ष के करोड़ों रुपए के दुरुपयोग के आरोपों की केन्द्रीय

जांच ब्यूरो द्वारा जांच करा रही है/जांच कराने की विचार रखती है;

(ख) क्या सरकार स्वतंत्र एंव निष्पक्ष जांच कराने के लिए जांच-प्रक्रिया पूरी होने तक कुलपति को उनके पद से हटाने का विचार रखती है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति तथा अन्य लोगों के खिलाफ कुछ शिकायतें भेजी हैं। इस मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक जांच की गई थीं तथा रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास भेज दी गई थीं। आयोग ने मंत्रालय से कुछ स्पष्टीकरण तथा विचार मांगे हैं जो भेजे जा रहे हैं। इसी बीच कुलपति के सेवानिवृत्त होने पर एक नये कुलपति की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है तथा उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है।

Education as a Fundamental Right

1157. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering to accept Education as a fundemental Right in the constitution; and

(b) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI HANOHAR JOSHI): (a) and (b) The report of the Parliamentary Standing Committee on the Constitution (Eighty-Third Amendment) Bill, 1997 is under examination. It is felt that a wider debate on the implications of the proposed legislation should be initiated.

फैजाबाद और इलाहाबाद के बीच चलने वाली "सरयू एक्सप्रेस" को "फास्ट पैसेंजर ट्रेन" में बदलना

1158. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फैजाबाद और इलाहाबाद स्टेशनों के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी "सरयू एक्सप्रेस" को "फास्ट पैसेंजर ट्रेन" के रूप में परिवर्तित करने का विचार रखती है जिससे कि उक्त रेलगाड़ी से छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री कम किराए पर यात्रा कर सकें;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त रेलगाड़ी दोनों स्टेशनों के मध्य स्थित लगभग सत्तर प्रतिशत स्टेशनों पर ठहरती है, क्या सरकार शीघ्र ही उसे "फास्ट पैसेंजर" घोषित करेगी जिससे अधिकाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो सकें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। 4125/4126 फैजाबाद-इलाहाबाद सरयू एक्सप्रेस गाड़ियां भागवर्ती 21 स्टेशनों में से केवल 10 स्टेशनों पर ठहरती हैं।

गाजियाबाद-मुरादाबाद रेल मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव

1159. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार गाजियाबाद-मुरादाबाद रेल मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाने का विचार रखती है; यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इकहरी रेल लाइन होने के कारण यात्री गाड़ियां और माल गाड़ियां कई घंटे विलंब से चलती हैं जिससे माल के परिवहन में अनावश्यक विलंब होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस लाइन को अगले दो वर्षों में बदलने के लिए बजट में विशेष प्रावधान करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी हां, कार्य प्रगति पर है और गाज़ियाबाद और हापुड़ के बीच प्रथम चरण में है और इसका दिसंबर, 2000 तक पूरा होने का लक्ष्य है हापुड़ मुरादाबाद के चरण—II का कार्य चरण I का कार्य पूरा होने पर शुरू किया जाएगा.

(ख) जी हां;

(ग) 1998-99 के बजट में 10 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई है। भाग (क) के उत्तर से